भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2433
दिनांक 13 मार्च, 2025

मध्य प्रदेश में इथेनॉल मिश्रित ईंधन

†2433. श्री विष्णु दत्त शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान प्रगति के अनुसार सरकार वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की मध्य प्रदेश में इथेनॉल मिश्रित ईंधन शुरू करने और विशेष रूप से पन्ना, कटनी जिलों और छतरपुर जिले के खुजराहो शहर में इथेनॉल के उत्पादन के लिए 2जी इथेनॉल जैव-रिफाइनरियां स्थापित करने की कोई योजना है ताकि गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018, वर्ष 2022 में यथासंशोधित, में अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2030 से घटाकर एथेनॉल सप्लाई वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य जून, 2022 में अर्थात् ईएसवाई 2021-22 के दौरान निर्धारित समय से पाँच माह पहले ही प्राप्त कर लिया। पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण ईएसवाई 2022-23 में और बढ़कर 12.06%, ईएसवाई 2023-24 में 14.60% तथा ईएसवाई 2024-25 में दिनांक 28 फरवरी, 2025 तक 17.98% हो गया। फरवरी, 2025 माह के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज द्वारा 19.68% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।

(ख) से (ग) एथेनॉल मिश्रण पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के ओएमसीज मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एथेनॉल की उपलब्धता के आधार पर 20% तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का वर्तमान में विक्रय कर रहे हैं। सरकार ने देश में लिग्नोसेल्युलोजिक जैवमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके उन्नत जैवईंधनों की परियोजनाओं की स्थापना करने के निमित्त एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए "प्रधान मंत्री जी-वन (जैव-ईंधन – वातावरण अनुकूल फल अवशेष निवारण) योजना" 2019, वर्ष 2024 में यथासंशोधित, को अधिसूचित किया था। इस योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक स्तर के कुल 14 प्रस्तावों और प्रदर्शन स्तर के 8 प्रस्तावों को संस्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसमें से वाणिज्यिक स्तर के कुल 8 प्रस्तावों और प्रदर्शन स्तर के 4 प्रस्तावों को संस्वीकृति प्रदान किया गया। इस योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

*****